

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 9/2017 –Integrated Tax

G.S.R. 1259(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.8/2017- Integrated Tax, dated the 14th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1156(E), dated the 14th September, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table –

- (i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63”;
----	--	--------------------------------

- (ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter”.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note: - The principal notification No.8/2017-Integrated Tax, dated the 14th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1156 (E), dated the 14th September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 10/2017- एकीकृत कर

सा.का.नि. 1260 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कराधेय सेवाओं की अंतरराज्यिक पूर्ति करने वाले व्यक्ति को, और जिसका, अखिल भारतीय आधार पर संगणित, सकल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :

परंतु संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष प्रवर्ग राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, ऐसी पूर्ति का, अखिल भारतीय आधार पर संगणित, सकल मूल्य दस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं होगा।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव